3 करोड़ युवाओं को रोजगार

पहले की सरकार नौकरी देने के नाम पर वसूली करती थी

लखनऊ, 15 जुलाई. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न रोजगार के अवसर थे और न ही पारदर्शी भर्ती व्यवस्था।

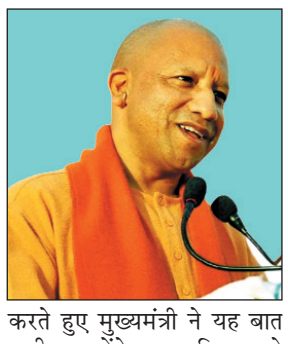

उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी था तथा तत्कालीन सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशगुन थी। विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के अवसर पर गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल विकास मिशन एवं आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पहले नौकरी निकलती नहीं थी और यदि निकलती भी थी तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल पड़ती थी। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकारों की सोच और कार्यशैली बीमार थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि सवा तीन करोड़ से अधिक युवाओं और कारीगरों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

> योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय का गठन कर इस क्षेत्र को नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि अब आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, ड्रोन, त्रि-आयामी मुद्रण (3डी प्रिंटिंग) और सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सुविधाएं केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, बलिया और बहराइच जैसे जिलों तक भी पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी लखनऊ में इसका कार्य जारी रहा और इससे लगभग 500 युवाओं को रोजगार मिला।

उन्होंने कहा कि यूनेस्को द्वारा इस वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस की थीम साझा भविष्य के लिए कौशल रखी गई है।

उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला प्रदेश है और सरकार इस जनसांख्यिकीय शक्ति को कौशल विकास से जोड़कर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर मजबूत करेंगे कौशल शिक्षा का ढांचा

नई दिल्ली. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और ऑस्ट्रेलियाई कौशल गुणवत्ता प्राधिकरण (एएसक्यूए) ने तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) में गुणवत्ता आश्वासन और नियामकीय सहयोग को मजबूत करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किये हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के महत्वपूर्ण परिणामों में एक और उपलब्धि जुड़ गयी है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

नोएडा : 5 मंजिला में आग, 2 की मौत

- ममूरा की रिहायशी इमारत में मची अफरा-तफरी
- बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकर लोगों को सुरक्षित निकाला

नोएडा, 15 जुलाई. नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा गांव में बुधवार को एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में 26 वर्षीय महिला स्नेहा और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के समय इमारत में करीब 50 परिवार मौजूद थे। आग लगते ही पूरे भवन में धुआं भर गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। मालिक (लैंडलॉर्ड) और लीजधारक (ऑपरेटर) को गिरफ्तार कर लिया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान इमारत के सामने स्थित दूसरी बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकर एक अस्थायी रास्ता बनाया गया। इसी रास्ते से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सक्रिय सहयोग किया। कई लोगों को धुएं से बचाने के लिए तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह पता लगाया जा रहा है कि आग किसी इलेक्ट्रिक बाइक में शॉर्ट सर्किट से लगी या एयर कंडीशनर में तकनीकी खराबी के कारण चिंगारी निकली। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्थानीय दुकानदार अमन ने सबसे पहले इमारत से धुआं और लपटें उठती देखीं।

मानहानि मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत

लखनऊ, 15 जुलाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बुधवार को राहत मिली। लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज राकेश यादव ने भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से दायर निगरानी याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। इस फैसले के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मानहानि मुकदमे की अंतिम बहस का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंतिम बहस की कार्यवाही लंबित है.

पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार

- पीएम मोदी ने साझा की तस्वीर

नई दिल्ली, 15 जुलाई. भारत रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार है. इसे स्वच्छ, हरित और शून्य-उत्सर्जन (जीरो एमिशन) परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, भारत की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है. उनकी इस पोस्ट के बाद इस परियोजना को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया है. यह परियोजना भारतीय रेलवे की 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' पहल का हिस्सा है. इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि विरासत (हेरिटेज) और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह पर्यावरण-अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराया जा सके.

> नई ट्रेन को 10 कोच वाले हाइड्रोजन-चालित डीईएमयू सेट के रूप में तैयार किया गया है. इसमें 682 सीटें हैं, जबकि कुल 2,600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है. परीक्षण के दौरान ट्रेन ने इससे अधिक गति हासिल की थी लेकिन नियमित संचालन के लिए इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. चूंकि यह अभी एक पायलट परियोजना है, इसलिए इसे नियंत्रित और सावधानीपूर्वक तरीके से शुरू किया जा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, हाइड्रोजन ट्रेनें चलते-फिरते बिजलीघर की तरह काम करती हैं.

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

- मेडिकल सुविधा को लेकर दाखिल हुई याचिका

नई दिल्ली, 15 जुलाई. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जारी भूख हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया।

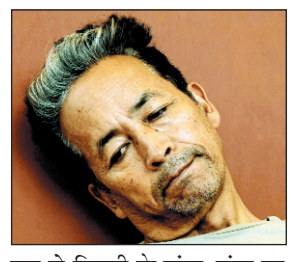

अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार सुबह तक यह बताने को कहा कि वांगचुक को जरूरी मेडिकल सुविधा और उपचार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। वह नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान उनकी तबीयत लगातार कमजोर होने की जानकारी सामने आई है.

राजनीतिक फेरबदल की चर्चाएं गर्म

फडणवीस के साथ राकांपा (शरदचंद्र) के नेताओं की देर रात बैठक

मुंबई, 15 जुलाई. महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में मंगलवार देर रात उस समय हलचल तेज हो गई जब दिवंगत अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ राकांपा (शरदचंद्र) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक निवास वर्षा पर एक बंद कमरे में बैठक की.

यह बैठक कथित तौर पर करीब सवा घंटे तक चली, हालांकि इसके एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है. यह घटनाक्रम राज्य में संभावित राजनीतिक फेरबदल को लेकर चल रही अटकलों के बीच सामने आया है. रिपोर्टों के अनुसार, राकांपा (शरदचंद्र) के प्रमुख शरद पवार अपनी भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विचार कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चाएं गर्म हैं कि उनकी पार्टी का एक धड़ा सत्ताधारी गठबंधन के करीब आ सकता है.

ऑपरेशन टाइगर को लेकर भी चर्चाएं

यह बैठक ऐसे समय में भी हुई है जब राज्य में ऑपरेशन टाइगर को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसके तहत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के छह सांसदों को अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। इस तरह की रिपोर्टें हैं कि शरद पवार खेमे के कई विधायक राजनीतिक अस्तित्व और विकास संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार में शामिल होने के इच्छुक हैं.

भरत तिवारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली, 15 जुलाई. बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में उचित राहत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया.

यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने इसी मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. यह याचिका प्रिया मिश्रा की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने दायर की थी. याचिका में एनकाउंटर की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई थी. इसके साथ ही सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने, एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को लगाई फटकार

नई दिल्ली, 15 जुलाई. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें कहा गया था कि किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश और उसकी छाती दबाना अपने आप में बलात्कार के प्रयास का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता और कानूनी प्रावधानों की गहन समझ जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ के सामने यह मामला सुनवाई के दौरान आया. अदालत ने कहा कि वह पटना हाईकोर्ट के इस आदेश पर विस्तृत आदेश जारी करेगी। यौन अपराधों पर न्यायिक संवेदनशीलता की जरूरत- सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को पटना हाईकोर्ट के 9 जुलाई के आदेश की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादास्पद फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ यौन हिंसा के मामले में कुछ कृत्यों को बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। अब पटना हाईकोर्ट के आदेश पर भी शीर्ष अदालत ने चिंता जताई है।

> राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट को मंजूरी- सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई में न्यायिक संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि न्यायाधीश यौन अपराधों की सुनवाई के दौरान उचित दृष्टिकोण अपना सकें।

एक नजर में

ममता के करीबी मदन मित्रा का इस्तीफा

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बुधवार को उस समय बड़ा राजनीतिक झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और कमरहाटी से विधायक मदन मित्रा ने अपने सभी संगठनात्मक दायित्वों से

इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियों के साथ-साथ विधानसभा में मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के पद से भी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ऋब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के साथ खड़े होने की घोषणा की। इस्तीफे के बाद मदन मित्रा ने कहा कि उनका मतभेद पार्टी संगठन के भीतर है, न कि पार्टी से। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपना कमरा बदला है, घर नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ममता बनर्जी के प्रति सम्मान रखते हैं और उनके साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला, जिसके लिए वह आभारी हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नगर निगम भर्ती मामले की जांच के सिलसिले में मदन मित्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को समन जारी किया है। हालांकि मदन मित्रा ने कहा कि उनके राजनीतिक फैसले का ईडी की कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है.

सुरक्षा बलों ने पीका गन के कारतूस बरामद किए

जम्मू. जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक ठिकाने से पीका गन के कारतूस बरामद किये. अधिकारियों ने बताया कि नियमित गश्त के दौरान विशेष अभियान समूह (एसओजी) की एक टीम ने मंडी तहसील के सवाजियान गगरांगा गांव में एक ठिकाने से पीका गन के 215 कारतूस बरामद किए. उन्होंने बताया कि गोला-बारूद ज़ब्त कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

हस्तियों के ट्वीट

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देते हुए सराहना किया है। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा महिलाओं का होना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है। खुदा वीमेन इन प्रोग्राम में शामिल ये युवा ऑस्ट्रेलियाई भी इसी का हिस्सा हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने हाल हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि हमारे सभी सैन्य कर्मियों और उन सभी लोगों का, जो हमारी सुरक्षा, देखभाल और एक-दूसरे का ख्याल रखने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, सभी फ्रांसीसी लोगों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। गणतंत्र अमर रहे, फ्रांस अमर रहे!

परिसीमन पर सुप्रिया सुले की शर्त

पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, फिर परिसीमन पर हो चर्चा

नई दिल्ली, 15 जुलाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को कहा कि संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने परिसीमन प्रक्रिया को लेकर किसी से कोई औपचारिक चर्चा नहीं की है और इस विषय पर सरकार की ओर से भी उनसे संपर्क नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंडिया ब्लॉक ने कभी परिसीमन की मांग नहीं की है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन से जुड़े किसी भी विधेयक पर उनकी पार्टी अपना रुख विधेयक पेश होने के बाद और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों से चर्चा के उपरांत तय करेगी। उन्होंने कहा कि डीएमके, समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी सहित कई दल पहले भी महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। सुले ने कहा कि उनकी प्राथमिक मांग महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की ओर से परिसीमन को लेकर कोई अलग मांग नहीं की गई है। उनके अनुसार, किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय पर गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले विपक्षी दलों की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया गया था कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए अलग-अलग दलों को अलग-अलग बुलाने के बजाय इंडिया ब्लॉक के सभी प्रतिनिधियों को एक साथ आमंत्रित किया जाए।

आज का इतिहास

1661: स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया.
1856: हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली.
1909: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का जन्म.
1945: अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया.
1951: नेपाल को ब्रिटेन से आजादी मिली.
1968: भारतीय हॉकी कप्तान धनराज पिल्लै का जन्म.
1990: यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की.
1992: डॉ. शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने.
1999: जॉन एफ़. केनेडी के पुत्र जॉन एफ़. केनेडी जूनियर की विमान दुर्घटना में मृत्यु.

आयोजन | सबके हित में धन समर्पित करने का आह्वान

देश हमें सब कुछ देता है, हम भी कुछ देना सीखें : शिवराज

नई दिल्ली, 15 जुलाई. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव. में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएसआर को भारतीय परंपरा की ट्रस्टीशिप भावना से जोड़ते हुए कहा कि देश हमें सब कुछ देता है, इसलिए कॉर्पोरेट जगत अपनी कमाई का हिस्सा किसानों, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण समाज के हित में समर्पित कर देश के विकास में साझेदार बने.

उन्होंने जोर देकर कहा कि रिसर्च लैब में कैद न रहे, बल्कि विज्ञान से किसान तक का पुल बने, ताकि जलवायु अनुकूल खेती, मृदा स्वास्थ्य, पोषण-सुरक्षित भोजन, कृषि कौशल विकास और महिला किसानों की उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सीएसआर निवेश से वास्तविक जमीन स्तर पर बदलाव दिखे. सीएसआर को 'ट्रस्टीशिप' की भावना से जोड़ा- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कॉन्क्लेव एक ऐसा समागम है जिसमें कॉर्पोरेट जगत, मंत्री, वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान सभी एक ही मंच पर जुड़े हैं, जैसे कृषि के लिए एक कम्पलीट वैल्यू चेन बन गई हो.

> उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि जिनके पास अधिक धन है, वे उसके मालिक नहीं, बल्कि ट्रस्टी हैं और वह धन मूलत: समाज का धन है. सीएसआर की भावना यही है कि जो कुछ भी उद्योग, व्यापार और कंपनियां अर्जित करती हैं, उसका एक हिस्सा देश और जनता के हित में स्वेच्छा से समर्पित किया जाए. उन्होंने साफ किया कि सरकार की सोच संसाधन छीनने की नहीं, बल्कि क्षमता और टैलेंट को अवसर देने की है, ताकि उद्यमी धन कमाएँ और फिर उसी धन का हिस्सा समाज, किसान और कृषिसंबंधित नवाचारों पर निवेश करें.

चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

14 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम

06 हजार यात्री हर दिन कर रहे बद्रीनाथ के दर्शन

बद्रीनाथ, 15 जुलाई. उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बावजूद चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और हजारों तीर्थयात्री रोजाना पवित्र तीर्थस्थलों के दर्शन कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है जबकि पहाड़ी राज्य के कई हिस्सों में मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है। अधिकारियों के अनुसार, हर दिन 6,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं.

वहीं मौजूदा तीर्थयात्रा सीजन के दौरान श्री केदारनाथ धाम में पूजा-अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 14 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि, अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है क्योंकि लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, ट्रेकिंग के रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, भूस्खलन हो रहा है और मौसम से जुड़ी अन्य चुनौतियां पैदा हो गई हैं।

> भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के विभिन्न हिस्सों, खासकर चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश व खराब मौसम की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए व्यापक इंतजाम जारी हैं। बद्रीनाथ धाम में पूजा-अर्चना करने के बाद एक श्रद्धालु ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हम यहां हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आए थे.